इकाई 13 ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक प्रयास

इकाई की रूपरेखा

13.0 लक्ष्य और उद्देश्य

13.1 परिचय

13.2 स्वैच्छिकता – अवधारणा का विकास

13.3 लोगों की भागीदारी और विकास

13.3.1 लोगों की भागीदारी का निर्धारण करने वाले कारक

13.3.2 लोगों की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक

13.4 स्वैच्छिक संगठन के प्रमुख प्रकार, भूमिका और कार्य

13.5 स्वैच्छिक संगठन (स्वैच्छिक संगठन) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

13.6 ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक संगठन और गैर-सरकारी संगठनों की पहल

13.6.1 राज्य सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन – कपार्ट और सीएसडब्ल्यूबी

13.6.2 स्वैच्छिक संगठन

13.7 स्वैच्छिक संगठनों की समस्याएं

13.8 स्वैच्छिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण

13.9 सारांश

13.10 मुख्य शब्द

13.11 संदर्भ-सूची

13.0 लक्ष्य और उद्देश्य

आपको पता ही होगा कि ग्रामीण समाज की समस्याएं बहुआयामी प्रकृति की होती हैं। इसलिए, ग्रामीण विकास के मुद्दे और विभिन्न पहलू भी बहुत जटिल हैं। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहु-एजेंसी और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में स्वैच्छिक प्रयासों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित में सक्षम हो पाएंगे:

- स्वैच्छिकता और इसके विकास की अवधारणा का वर्णन करने में;
- विभिन्न प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का वर्णन करने में;
- स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अंतर करने में;
- स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका पर चर्चा करने में;
- कपार्ट की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करने में;
- स्वयंसेवी संगठनों की समस्याओं को स्पष्ट करने में; और
- स्वैच्छिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक प्रयासों का सुझाव देने में ।

13.1 परिचय

धीरे-धीरे यह महसूस किया गया है कि अकेले सरकार ग्रामीण लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। विकास की प्रक्रिया में मानवीय कारकों को सक्रिय/प्रेरित करने के लिए इसके लिए बहुत सारे संगठनात्मक और अवसंरचनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि स्वैच्छिक प्रयास हमेशा भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग रहे हैं। इस प्रकार यह भारतीय समाज में गहराई से निहित है। नतीजतन, स्वैच्छिक प्रयास समाज/समुदाय की जरूरतों और आकांक्षाओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। इस इकाई में स्वैच्छिकता की अवधारणा, उसके विकास, स्वैच्छिक संगठन के प्रकार, स्वयंसेवी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अंतर, इसके प्रचार में सरकारी पहल, स्वैच्छिक संगठनों के सामने आने वाली समस्याओं और उन्हें मजबूत करने के लिए आवश्यक पहलों से आपको परिचित कराने का प्रयास किया गया है।

13.2 स्वैच्छिकता : अवधारणा का विकास

स्वैच्छिक प्रयास अन्य साथी प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से एक प्रयास है। इसमें समुदाय के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के प्रयास में लोगों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। स्वैच्छिक प्रयास का उद्देश्य लोगों को अपने संसाधनों को जुटाकर खुद की मदद करने में मदद करना और उनके लक्ष्यों को साकार करने के लिए उन्हें लागू करके उनकी समस्याओं के सामूहिक समाधान खोजने की उनकी क्षमता का दोहन करना है। यह अक्सर लोगों को जुटाने और उन्हें कुछ विकास-उन्मुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रयासों का परिणाम होता है। स्वैच्छिक प्रयास हमेशा राज्य की वर्तमान नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप या संगत नहीं होना चाहिए। इस तरह के कई स्वैच्छिक प्रयास सामाजिक सक्रियता की प्रकृति के हैं जिसमें व्यक्ति और समूह अन्यायपूर्ण राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के विरोध में खुद को संगठित करते हैं जो विकास के मुद्दों की उपेक्षा करते हैं, विशेष रूप से सीमांत समूहों से संबंधित, और एक ही समय में वर्तमान सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों और संरचनाओं में बदलाव की तलाश करना।

आइए हम स्वैच्छिक प्रयास की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें।

i) **लोगों की भागीदारी**

अपने सही अर्थों में, लोगों की भागीदारी का अर्थ है सभी चरणों में लोगों की भागीदारी, यानी योजना, कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन, निर्णय लेना, लाभों को साझा करना, निगरानी और मूल्यांकन। लोगों की भागीदारी से परिकल्पित और विकसित विकास कार्यक्रम जमीनी हकीकत के करीब हैं। क्योंकि वे समुदाय में निहित हैं और अपनी गतिविधि के रूप में माने जाते हैं। जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी की वकालत इस दृष्टिकोण से की जाती है कि यह लोगों को सशक्त बनाने और इसे टिकाऊ बनाने के लिए स्थिति में सुधार लाने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। कभी-कभी स्वैच्छिक प्रयास का उपयोग लोगों की भागीदारी के साथ परस्पर किया जाता है। हालांकि, दोनों शब्दों में बहुत समानता है लेकिन वे काफी समान नहीं हैं। आइए हम इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। लोगों का एक समूह प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के लिए काम करने का निर्णय

ले सकता है और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक स्वैच्छिक संगठन स्थापित करना चाहता है। इसे एक स्वैच्छिक प्रयास माना जाएगा। संगठन कार्यक्रमों की योजना बनाएगा और रणनीतियों का खाका तैयार करेगा। यह योजना, कार्यक्रम निर्माण और निगरानी और मूल्यांकन के उपकरण विकसित करने की प्रक्रिया में लोगों को शामिल नहीं कर सकता है। हालांकि, यदि स्वैच्छिक संगठन के कार्यक्रम को प्रभावी होना है, तो इसके लिए समुदाय के सदस्यों और प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी यानी परियोजना निर्माण से मूल्यांकन तक सभी चरणों में लोगों की भागीदारी।

ii) तीसरा क्षेत्र

एक सामाजिक संदर्भ में, स्वैच्छिक संगठन ''तीसरे क्षेत्र'' का गठन करते हैं, पहला और दूसरा ''सरकार'' और ''बाजार'' या निजी व्यवसाय है। ''तीसरे क्षेत्र'' (स्वैच्छिक संगठन) को ''स्वतंत्र क्षेत्र'' के रूप में भी जाना जाता है, जो सरकार और निजी व्यवसाय के दायरे के बाहर स्वतंत्र बल के रूप में स्वैच्छिक संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है, हालांकि वित्तीय संदर्भ में, यह क्षेत्र निर्भर करता है यह सरकारी और निजी दोनों व्यवसायों पर भारी है।

महत्वपूर्ण कारक जो एक साधारण संगठन को ''स्वैच्छिक संगठन'' से अलग करता है, वह महत्वपूर्ण इनपुट है जो स्वयंसेवक संगठन के प्रबंधन और संचालन को देते हैं। यह वह कारक है जो स्वैच्छिक संगठन को अन्य सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाम ''गैर-लाभकारी'' या ''गैर-लाभकारी'' संगठन (एनपीओ) देता है। ''गैर-लाभकारी'' या ''गैर-लाभकारी'' इस तथ्य पर जोर देता है कि संगठन मुख्य रूप से अपने मालिकों, प्रबंधकों या सदस्यों के लिए लाभ उत्पन्न करने के लिए मौजूद नहीं है।

कुछ स्वैच्छिक संगठन ''निजी'' शब्द भी उपयोग कहते हैं और खुद को निजी स्वैच्छिक संगठन कहते हैं। निजी, यहां, इंगित करता है कि संगठन संस्थागत रूप से सरकार से अलग है। इसलिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट) आदि जैसे सरकार द्वारा गठित संगठन निजी स्वैच्छिक संगठन श्रेणी में नहीं आते हैं। कुछ स्वैच्छिक संगठन खुद को गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कहना पसंद करते हैं। यह एक बार फिर इस बात पर जोर देने के लिए आवश्यक है कि संगठन सरकार या किसी अन्य बाहरी एजेंसी द्वारा नियंत्रित नहीं है।

iii) विशेषताएं

स्वैच्छिक प्रयास और लोगों की भागीदारी को अक्सर स्वैच्छिक संगठन की स्थापना के माध्यम से संस्थागत किया जाता है। आपके पास अब तक स्वैच्छिक संगठन की विशेषताओं की कुछ धारणा हो सकती है। आइए अब हम कोशिश करना और उनकी गणना करना:

- स्वैच्छिक संगठन का गठन, कल्याण और विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की पहल के माध्यम से किया जाता है, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के। इन व्यक्तियों में प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना होती है और वे सामाजिक चेतना से प्रेरित होते हैं।

- स्वैच्छिक संगठन की सदस्यता पूरी तरह से स्वैच्छिक है। जबकि कुछ स्वैच्छिक संगठन के पास रुचि के विशिष्ट क्षेत्र हो सकते हैं, अन्य में मैक्रो-स्तर और अधिक वैश्विक उद्देश्य हो सकते हैं ।
- स्वैच्छिक संगठन लाभ कमाने के लिए न तो बनते हैं और न ही चलाए जाते हैं।
- स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं और सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य नहीं करते हैं। हालांकि, कुछ स्वैच्छिक संगठन सरकार से सहायता अनुदान मांगते हैं, जिसके लिए उन्हें सहायता अनुदान नियमों में इंगित कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- अधिकांश स्वैच्छिक संगठन 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या राज्य सरकारों के इसी तरह के अधिनियमों के तहत पंजीकृत हैं। इस तरह के पंजीकरण उन्हें सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने का अधिकार देते हैं।

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में स्वैच्छिक संगठन का महत्व स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित आधारों पर महत्वपूर्ण माना गया है :

- स्वैच्छिक संगठन के पास जमीनी स्तर पर समुदाय और संसाधनों की जरूरतों और समस्याओं का पहला अनुभव और ज्ञान है।
- स्वैच्छिक संगठन जमीनी स्तर पर लोगों के करीब हैं।
- स्वैच्छिक कार्रवाई की प्रतिबद्धता और उत्साह विकास कार्यों को गति देता है।
- स्वैच्छिक संगठन कठोर नौकरशाही प्रणाली के विपरीत तेजी से सेवाएं प्रदान करते हैं।
- स्वैच्छिक क्षेत्र अधिक उत्तरदायी है और अधिक लचीलेपन के साथ काम कर सकता है।
- स्वैच्छिक कार्रवाई लागत प्रभावी है क्योंकि इसमें एक जटिल नौकरशाही सेट-अप नहीं है।

13.3 लोगों की भागीदारी और विकास

भागीदारी का मतलब लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी है, न कि प्रतिनिधित्व के माध्यम से अप्रत्यक्ष भागीदारी। भागीदारी को भागीदारी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए:

i) निर्णय,

ii) विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,

iii) कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन, और

iv) विकास के लाभ को साझा करना।

विकास के संदर्भ में भागीदारी की दो अलग-अलग व्याख्याएं नीचे दी गई हैं :

1) विकास के लिए एक इनपुट के रूप में भागीदारी।

2) भागीदारी ग्रामीण विकास में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने का एक साधन है।

इस प्रकार, भागीदारी को केवल सुविधा के उपकरण के बजाय विकास की प्रक्रिया के आंतरिक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमें भागीदारी की आवश्यकता है, क्योंकि इससे सेवाओं की स्वीकार्यता और उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलती है। यह लगातार संसाधनों की कमी का सामना कर रहे क्षेत्र को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है क्योंकि समुदाय को एक अप्रयुक्त संसाधन आधार के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा सेवाओं को विशेष रूप से वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। लोगों की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि यह विकास में बाधा डालने वाली मौजूदा संरचना को तोड़ने और इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के साथ बदलने में मदद करती है जिन्हें विकास के साथ असंगत माना जाता है ।

13.3.1 लोगों की भागीदारी का निर्धारण करने वाले कारक

लोगों की भागीदारी की प्रक्रिया तीन मान्यताओं पर आधारित है जैसा कि नीचे दिया गया है :

- एक समुदाय के रूप में लोग अपने स्वयं के विकास के लिए जिम्मेदारी को जानते हैं, तथा इसे महसूस और स्वीकार करते हैं।
- लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का दोहन और विकास करते हैं, इसमें कार्मिक और भौतिक संसाधन, पेशेवर और पारंपरिक आदि शामिल हैं। इसमें निजी और सरकारी प्रयास, संस्थान और संगठन, स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय भी शामिल हैं।
- प्राथमिक ध्यान लोगों द्वारा अपनी समस्याओं, संसाधनों और सामुदायिक प्राथमिकताओं के अनुसार कार्रवाई में रखा जाता है।

अब हम लोगों की भागीदारी की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों को देखते हैं।

i) **चेतनाकरण :** चेतना का अर्थ है महत्वपूर्ण जागरूकता के निर्माण की प्रक्रिया। यह इस सिद्धांत पर स्थापित किया गया है कि सभी मनुष्य किसी भी प्रकार की स्थितिजन्य समस्याओं से खुद को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं–चाहे वह भाग्यवादी हो या नियतात्मक। यह लोगों के लिए गहरी मानवतावादी चिंता के आधार पर महत्वपूर्ण जागरूकता के निर्माण के बारे में है। जिन लोगों का शोषण किया जा रहा है या अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जा रहा है, वे स्थिति पर प्रतिबिंबित कर सकते हैं और अपने स्वयं के दृष्टिकोण से अपनी जरूरतों का आकलन कर सकते हैं। गरीबों और मजलूमों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्हें अपनी दुर्दशा पर प्रतिबिंबित करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। गहरे संकट की प्राप्ति के आधार पर, दमनकारी ताकतों से मुक्त करने के लिए उचित कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार, चेतना एक जागरूकता निर्माण शिक्षा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने स्वयं के पर्यावरण को समझता है, व्याख्या करता है, आलोचना करता है और अंत में बदल देता है। डेविड हिलवुड के शब्दों में, ''विज्ञान चेतना का जागरण है, किसी व्यक्ति की अपनी पहचान और स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण जागरूकता का विकास, अपनी स्थिति के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करने और उस वास्तविकता को बदलने के लिए तार्किक और चिंतनशील रूप से कार्य करने की क्षमता का पुनः जागरण करना।

ii) **संगठन** : लोगों की भागीदारी की प्रक्रिया में शामिल अगला कदम संगठन है। संगठन कार्रवाई से पहले आता है। संगठन स्वैच्छिक कार्रवाई भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी समस्याओं को हल करने का उद्देश्य के साथ आते हैं। इस प्रक्रिया में, वे अपनी जरूरतों या उद्देश्यों की पहचान करते हैं और प्राथमिकताओं के अनुसार उन्हें रैंक करते हैं क्योंकि सभी जरूरतों को तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता है। जिन साधनों से उनकी जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है, उनकी भी पहचान की जाती है। उपलब्ध और आवश्यक दोनों संसाधनों की पहचान की जाती है। की जाने वाली कार्रवाई के प्रकार को भी अंतिम रूप दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत सामुदायिक एकीकरण और बातचीत प्रदान करती है।

इसलिए यह उपयुक्त संगठनात्मक संरचना के डिजाइन पर जोर देता है जो लक्ष्यों, कार्यों, संसाधन संबंधों आदि से बना है।

iii) **कार्रवाई :** विश्लेषण में हमने उन चरणों को देखा है जो लोगों की भागीदारी की प्रक्रिया में कार्रवाई से पहले हैं। उपाय या कार्रवाई करना अंतिम चरण है जिसमें लोगों को वह हासिल करने का मौका दिया जाता है जो वे चाहते हैं। ग्रामीण विकास के संदर्भ में कार्रवाई को मोटे तौर पर तीन घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात,

क) उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं का प्रभावी उपयोग,

ख) अधिक और बेहतर सेवाओं के प्रावधान की मांग, और

ग) बेहतर सामाजिक संरचना का निर्माण।

13.3.2 लोगों की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक

उपरोक्त विश्लेषण में हमने लोगों की भागीदारी के अर्थ और प्रक्रिया को देखा है। यहां भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। कई कारकों में से, हम 1984 में राष्ट्रीय श्रम संस्थान, दिल्ली में आयोजित असंगठित ग्रामीण श्रम के आयोजन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में पहचाने गए कारकों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस संगोष्ठी के अनुसार निम्नलिखित कारक लोगों की भागीदारी को बाधित कर रहे हैं।

i) उचित वर्ग की बलपूर्वक शक्ति जिसका उद्देश्य गरीबी को दूर करना नहीं है, बल्कि देश, यह सुनिश्चित करना है कि जनता की आय कम रखी जाए और सामाजिक सेवाएं उनके लिए प्रतिबंधित हों।

ii) अमीरों में गरीबों की आर्थिक निर्भरता और भारतीय समाज के गरीब वर्गों की विविधता के बीच जटिल संबंध।

iii) यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्थानीय कानून और व्यवस्था मशीनरी का अंतर्निहित पूर्वाग्रह।

iv) सहायक कानून की कमी और गरीबों के पक्ष में अधिनियमित मौजूदा सामाजिक कानूनों का कार्यान्वयन न होना।

v) नौकरशाही के निचले स्तर का नकारात्मक और दमनकारी रवैया और गरीबों के आयोजकों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग।

इन कारकों के अलावा सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग या सामाजिक नेतृत्व की ''इच्छा'' गरीबों के विकास की प्रक्रिया में यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह माना गया है कि गरीबी उन्मूलन के वर्तमान कार्यक्रमों को ग्रामीण गरीबों के सामूहिक उपक्रमों और इन वर्गों द्वारा सामूहिक कार्रवाई से सम्पूरित किए जाने की आवश्यकता है। जब गरीब स्वयं जागरूक हो जाएंगे, अपनी शैक्षिक क्षमताओं में सुधार करेंगे और संगठित होंगे, तो गरीबी हटाने के लिए सहभागी रणनीतियों का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

अपनी प्रगति की जाँच करें 1

नोटः क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ख) पाठ के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें।

1) अपने शब्दों में, लोगों की भागीदारी को निर्धारित करने वाले कारकों को सही ठहराएं।

.....

.....

.....

.....

.....

13.4 स्वैच्छिक संगठन के प्रमुख प्रकार, भूमिका और कार्य

दृष्टिकोण और कार्यों के अनुसार, स्वैच्छिक संगठन को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता हैः

i) **कल्याण संगठन** : इनका उद्देश्य समुदाय की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना है, जैसे भोजन, आश्रय और शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करना। अक्सर इन संगठनों को धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

ii) **राहत और पुनर्वास** : वे संगठन जो प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा, अकाल) और मानव निर्मित आपदाओं (आग, युद्ध के विनाश, सांप्रदायिक दंगों) से उत्पन्न समस्याओं का जवाब देते हैं। उनके कार्य तब तक जारी रहते हैं जब तक पीड़ितों का पुनर्वास नहीं हो जाता।

iii) **कार्यकर्ता संगठनः** ये संगठनों का कट्टरपंथी रूप हैं। ऐसे संगठनों में शामिल कर्मी सामाजिक कार्रवाई में विश्वास करते हैं। उनका मुख्य कार्य लोगों को संतुष्ट करना और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में उनकी सहायता करना है।

स्वैच्छिक संगठन की भूमिका और कार्य

देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं इतनी विशाल और बहुआयामी हैं कि सरकारी प्रशासनिक मशीनरी अकेले उनसे निपट नहीं सकती है। आत्मनिर्भर समाज की स्थापना का अर्थ है कि सरकार पर लोगों की निर्भरता को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, विकास का अर्थ 'मनुष्यों' की भागीदारी को शामिल करने के लिए

व्यापक हो जाती है। गुणात्मक परिवर्तन पर जोर दिया जा रहा है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी शामिल है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में, विकास का अर्थ विशेष रूप से केवल जरूरतमंद लोगों को दिए गए लाभों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आबादी अपने भाग्य पर अधिक महारत हासिल करती है। यह केवल आर्थिक जीवन में ऐसे परिवर्तन हैं जो बाहर से मजबूर नहीं होते हैं, बल्कि भीतर से अपनी पहल के माध्यम से उत्पन्न होते हैं ।

उपरोक्त के आलोक में, यह कहा जा सकता है कि स्वैच्छिक संगठन परिवर्तन और विकास के लिए सही प्रकार का वातावरण बनाने के लिए उपयुक्त एजेंसियां हैं। कोई यह भी कह सकता है कि नीचे वर्णित कुछ विशेषताओं के कारण स्वैच्छिक संगठन को सरकार पर बढ़त भी है:

- स्वैच्छिक संगठन, नौकरशाही और पदानुक्रमित बाधाओं से छोटे और स्वतंत्र होने के नाते काफी हद तक लचीले हैं। वे स्थानीय मांगों के लिए तेजी से और कुशलता से जवाब दे सकते हैं। स्थानीय रूप से आधारित होने के नाते, वे स्थानीय पर्यावरण के बारे में जानते हैं और इसके प्रति उत्तरदायी हैं। वे बदलती ग्रामीण परिस्थितियों के लिए अपने काम करने की शैली को अनुकूलित कर सकते हैं। वे आम तौर पर स्थानीय क्षेत्रों के लोगों को नियुक्त करते हैं जो स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं से परिचित हैं।

- स्वैच्छिक एजेंसियां नई जरूरतों या अपूर्ण जरूरतों की तलाश में जाती हैं, और उन्हें खोजने के बाद उन्हें अपने तरीके से पूरा करने के लिए संघर्ष करती हैं। वे जनता की राय बनाते हैं और यदि आवश्यक हो तो वे राज्य से कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। वे तीन तरीकों से सार्थक भूमिका निभा सकते हैं।

  i) ग्रामीण आबादी को विकासात्मक दृष्टिकोण की ओर उत्प्रेरित करना,

  ii) मॉडल बनाएं, नए कार्यक्रमों के साथ प्रयोग करना और नवप्रवर्तकों के रूप में कार्य करना, और

  iii) स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं की पहचान करके क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करना।

  स्वैच्छिक संगठन को तीन मामलों में आधिकारिक एजेंसियों से संभावित रूप से बेहतर माना जाता है,

  क) उनके कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारियों की तुलना में गरीबों के कष्टों को कम करने के कार्य के लिए अधिक ईमानदारी से समर्पित हैं;

  ख) सरकारी कर्मचारियों की तुलना में ग्रामीण गरीबों के साथ उनका बेहतर तालमेल है; और

  ग) उन्हें लोगों की जरूरतों का जवाब देने की स्वतंत्रता है।

आप कुछ क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत हो सकते हैं या याद कर सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:

- भूमिहीन मजदूरों को उचित मजदूरी की व्यवस्था करना;

- हरिजन के अपमान और सभी प्रकार के शोषण को रोकने का प्रयास;
- बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास;
- दहेज विरोधी अभियान चलाना आदि।

पूर्वगामी विश्लेषण में आपने मुख्य रूप से संरचनात्मक लाभों के आधार पर स्वैच्छिक संगठन की क्षमता देखी है। स्वैच्छिक संगठन का एक अद्वितीय कार्य विकास की प्रक्रिया में लोगों को शामिल कर रहा है।

13.5 स्वैच्छिक संगठन (वीओ) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

स्वैच्छिक संगठन और गैर-सरकारी संगठनों के बीच मतभेदों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके अर्थ के संदर्भ में बहुत भ्रम मौजूद है। कुछ लेखकों ने गैर-सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक संगठन के अंतर्गत शामिल किया है, जबकि अन्य एनजीओ को स्वैच्छिक संगठन से अलग मानते हैं। यह मुख्य रूप से है क्योंकि दोनों में एक बात समान है, यानी स्वैच्छिकता। ग्रामीण विकास के संदर्भ में जब हम स्वैच्छिक संगठन के बारे में बात करते हैं, तो गैर-सरकारी संगठनों को आम तौर पर शामिल किया जाता है। हालांकि, मतभेद बने हुए हैं और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आइए हम संक्षेप में उनका अध्ययन करें।

स्वैच्छिक संगठन और गैर-सरकारी संगठन दोनों अपने उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, कामकाज के अध्ययन, कानूनी स्थिति, सामाजिक-राजनीतिक अभिविन्यास और आर्थिक ताकत आदि के संबंध में व्यापक रूप से भिन्न हैं। स्वैच्छिक संगठन काफी हद तक सरकार से स्वतंत्र हैं और मुनाफा कमाने वाले उद्यम नहीं हैं। स्वैच्छिक संगठन को बड़े पैमाने पर नागरिकों के एक संघ द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। हालांकि, गैर-सरकारी संगठन राज्य के अन्य संगठनों से अलग हैं। गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न एजेंसियों से वित्त पोषण के लिए पात्र होने के लिए, इसे कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए।

13.6 ग्रामीण विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों की पहल

एक गलत प्रचलित दृष्टिकोण है कि स्वैच्छिक संगठन और सरकारी एजेंसियां समानता के रूप में कार्य करती हैं, इसको सुधारने की आवश्यकता है। वास्तव में, सरकार ग्रामीण समस्याओं को हल करने के अपने प्रयास में स्वैच्छिक संगठन और गैर सरकारी संगठनों की सहायता और सुविधा प्रदान करती थी। इस प्रकार ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। राज्य निम्नलिखित नीतिगत उपायों के माध्यम से स्वस्थ संबंधों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकते हैं:

- सामाजिक नीतियों को एक स्वस्थ नागरिक समाज के निर्माण का प्रयास करना चाहिए;
- राज्य संस्थानों की सार्वजनिक जवाबदेही;
- कराधान नीतियां – स्वैच्छिक संगठन को प्रोत्साहन प्रदान करना;

- स्वैच्छिक संगठन की मदद और सुविधा के लिए विनियमन;
- भ्रष्टाचार का उन्मूलन, प्रतिबंधात्मक कानून और प्रक्रियाएं।

स्वैच्छिक कार्रवाई : स्वैच्छिक संगठनों के साथ राज्य का सहयोग साबित हुआ है

ट्रैक रिकॉर्ड. इस तरह स्वैच्छिक संगठन अपने एजेंडे के प्रति सच्चे और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति जवाबदेह बने रहते हैं–

- सार्वजनिक परामर्श में स्वैच्छिक संगठन को भूमिका की पेशकश करना, उनके नेताओं को आधिकारिक आयोगों में सेवा करने के लिए आमंत्रित करना, सूचना का प्रसार आदि;
- राज्य को आपसी सम्मान के आधार पर समन्वय के तंत्र तैयार करने चाहिए और स्वैच्छिक क्षेत्र पर अनावश्यक रूप से हावी नहीं होना चाहिए;
- स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वतंत्रता और स्वायत्तता से समझौता किए बिना प्रदर्शन के आधार पर राज्य निधि का प्रावधान; और
- स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आवश्यक जनशक्ति के प्रशिक्षण में सहायता करना।

13.6.1 राज्य सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनः कपार्ट और सीएसडब्ल्यूबी

हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि स्वैच्छिक संगठन और गैर-सरकारी संगठन दोनों ग्रामीण विकास के संदर्भ में समान कार्य कर रहे हैं। आइए हम एक गैर-सरकारी संगठन, अर्थात् कपार्ट और सीएसडब्ल्यूबी के एक विशिष्ट मामले का अध्ययन करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि गैर-सरकारी संगठनों के संचालन के लिए फोकस के क्षेत्र क्या हैं।

1) **जन कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद (कपार्ट)**

कपार्ट का मुख्य ध्यान ग्रामीण विकास के लिए नए उपयुक्त तकनीकी आदानों को पेश करना है। यह ग्रामीण विकास के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के उत्पादन और प्रसार के लिए एक समन्वय एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है।

इसका एक मुख्य कार्य विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों विशेष रूप से स्वैच्छिक संगठनों के विकास प्रयासों और पायलट परियोजनाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सर्वांगीण विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, जागरूकता पैदा करने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से परियोजनाओं/योजनाओं के आयोजन, मार्गदर्शन, विकास और समन्वय में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इनके अलावा कपार्ट को गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के लाभार्थियों को संगठित करने के लिए एक विशेष योजना चलाने का कार्य भी सौंपा गया है। इस योजना की परिकल्पना भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सातवीं योजना स्कीम के रूप में की गई थी।

प्रशासन : योजना की निगरानी तीन स्तरों पर की जाती है। केंद्रीय स्तर पर यह योजना कपार्ट के माध्यम से निष्पादित की जाती है जो परियोजना प्रस्तावों को संसाधित करती है ।

राज्य स्तर पर, इसे अन्य चिन्हित मॉडल गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है। जिला और ग्राम स्तर पर यह योजना नेहरू युवक केंद्रों, स्वैच्छिक संगठनों, महिला विकास केंद्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवी सेवा जैसे संस्थानों के माध्यम से लागू की जाएगी।

लक्ष्य समूह : समूह निम्नलिखित से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से बने होंगे:

क) कृषि मजदूर;

ख) बंधुआ मजदूरी;

ग) आईआरडी लाभार्थी;

घ) ग्रामीण कारीगर;

ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति;

च) एनआरईपी और आरएलईजीपी योजनाओं पर श्रमिक; और

छ) छोटे और सीमांत किसान।

रणनीति : कार्यान्वयन की रणनीति मोटे तौर पर तीन चरणों में होगी।

चरण – 1 : आयोजकों की पहचान विभिन्न गैर-सरकारी एजेंसियों/संगठनों से की जाएगी जैसे कि ऊपर उल्लिखित। आयोजक को कपार्ट द्वारा चिन्हित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों/एजेंसियों में गहन फील्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षुओं की पहचान कपार्ट के समर्थन से ग्रामीण अभिविन्यास शिविरों की योजना और कार्यान्वयन में शामिल इन गैर-सरकारी संगठनों/एजेंसियों द्वारा की जाएगी।

चरण – 2 : आयोजक ब्लॉक और ग्राम स्तर पर लाभार्थियों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे। उन शिविरों में प्रतिभागी लाभार्थियों, आयोजकों, प्रशिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक और गैर-सरकारी एजेंसियों और ग्राम स्तर के सरकारी अधिकारियों के समूह होंगे। इन जागरूकता शिविरों का उद्देश्य चेतना के स्तर को बढ़ाना, योजनाओं के ज्ञान को बढ़ाना और लाभार्थी समूहों के बीच समूह गठन और कार्रवाई के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना होगा।

चरण – 3 : इस चरण में समूह की नियमित बैठकें और सरकार की विभिन्न एजेंसियों और विंगों के साथ संपर्क शामिल होगा। यह एक सतत प्रक्रिया होगी जो अंततः एकजुट समूहों के उद्भव में समाप्त होगी। आयोजक, इन नियमित बैठकों के दौरान, यह देखने के लिए स्थितियां बनाएगा कि समूह का नेतृत्व समूह के भीतर से ही फेंक दिया जाए। एक सामान्य आर्थिक गतिविधि के आसपास बुने गए कार्यात्मक समूहों में सफलता की बेहतर संभावना होती है, और इसलिए, ऐसे समूहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंततः, यह उम्मीद की जाती है कि ये समूह आत्मनिर्भर बनेंगे।

2) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB)

यह प्रमुख राज्य वित्त पोषण एजेंसियां हैं जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के क्षेत्र में काम करने वाले पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान

करती हैं। यह महिला और बाल विकास विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। इसका राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में इसकी शाखाओं के रूप में कार्य करता है। महिला साक्षरता, स्व-सहायता समूहों का स्वैच्छिक कार्यगठन, रोजगार और आय सृजन गतिविधियां, जेंडर संवेदीकरण, महिलाओं और बालिकाओं पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण के क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इसका राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है।

13.6.2 स्वैच्छिक संगठन

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं। जागरूकता लाने, लोगों की लामबंदी, आत्मनिर्भरता और सतत विकास आदि में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

1) हिंद स्वराज ट्रस्ट – अन्ना हजारे की प्रेरणा ने सतत विकास रालेगण सिद्धि लाने के लिए स्थानीय समुदाय की अभूतपूर्व आत्म-लामबंदी पैदा की।

2) स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) – इसने संघर्ष और विकास की दोहरी रणनीतियों के माध्यम से गरीब स्व–नियोजित महिलाओं को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया। सेवा बैंक का योगदान और गरीब स्व-नियोजित महिलाओं के लिए सूक्ष्म ऋण के लिए इसका अभिनव एकीकृत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

3) प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN) – ग्रामीण लोगों के व्यापक लाभ के लिए प्रौद्योगिकियों के अवमूल्यन और स्केलिंग में इसका योगदान महत्वपूर्ण है।

4) सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र (SEARC) – यह तिलोनिया, राजस्थान में ग्रामीण समुदायों को सतत विकास प्रदान करने में सफल रहा है। सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र ने प्रदर्शित किया है कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में औपचारिक शिक्षा या व्यावसायिक डिग्री अब आवश्यक नहीं है।

5) तरुण भारत संघ (टीबीएस) – इसने ग्रामीण समुदायों में उनके लिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ अस्तित्वगत संबंध के मूल्य के बारे में एक राष्ट्रीय जागृति पैदा की है। तरुण भारत संघ ने राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल संचयन संरचनाओं का कायाकल्प किया है। तरुण भारत संघ ने भीकमपुरा और उसके आसपास के ग्रामीण समुदायों के बीच सामाजिक-आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और एकजुटता को सफलतापूर्वक प्रदान किया है।

6) इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वैच्छिक संगठन और गैर सरकारी संगठनों दोनों का समुदाय को शामिल करके और उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद करके ग्रामीण क्षेत्र के विकास का एक सामान्य उद्देश्य है। गैर-सरकारी संगठन विकास कार्यक्रमों की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तरफ स्वैच्छिक संगठन और दूसरी तरफ सरकार के बीच आवश्यक लिंक प्रदान करते हैं। अंतिम विश्लेषण में यह महत्वपूर्ण है कि स्वैच्छिक संगठन, गैर-सरकारी संगठन और सरकार सभी एक ही लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें 2

नोट: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ख) पाठ के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) स्वैच्छिक संगठन और गैर-सरकारी संगठन को अलग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13.7 स्वैच्छिक संगठनों की समस्याएं

- आपको यह आभास नहीं होना चाहिए कि स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ावा देने और समर्थन करने और स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान के लिए विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की आधिकारिक नीति के कारण, उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान किया गया है। यह सच्चाई से बहुत दूर है। अब बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठन को उपलब्ध सहायता अनुदान के बावजूद, उनमें से अधिकांश अभी भी वित्तीय संसाधनों की कमी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं जो उनके कामकाज को बाधित करता है। कभी-कभी, वित्तीय संसाधनों की कमी उतनी गंभीर बाधा नहीं हो सकती है जितनी कि निरंतर आधार पर सुनिश्चित धन की कमी। इस समस्या के कारण, कुछ स्वैच्छिक संगठन को एक गतिविधि को आधे रास्ते में छोड़ने और दूसरे को लेने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए धन उपलब्ध है। कुछ स्वैच्छिक संगठन विदेशी फंडों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं जो अनिश्चित हैं। फंडिंग एजेंसियों की अपनी धारणाएं हैं और अक्सर स्वैच्छिक संगठन पर अपनी प्राथमिकताओं और कार्यक्रम डिजाइनों को लागू करते हैं। सरकार या सहायता एजेंसियों से तदर्थ अनुदान उन्हें विभिन्न प्रकार के असंबद्ध कार्यक्रमों को चलाने वाले फेसलेस निकायों तक सीमित कर देते हैं। इससे निरंतरता और विस्तार दोनों को खतरा है।

- स्वैच्छिक संगठन को नेतृत्व की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जैसा कि स्वैच्छिक संगठन अपनी गतिविधियों के क्षेत्र और दायरे का विस्तार करते हैं, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व अक्सर संगठन चलाने में अभिभावी शक्तियों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। पहल करना और निर्णय लेना शीर्ष पर कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन जाता है। यह बढ़ता केंद्रीकरण कामकाज के लचीलेपन को प्रभावित करता है, निर्णय लेने के लोकतंत्रीकरण में बाधा डालता है और नए नेताओं के उद्‌भव में बाधा डालता है और टीम-वर्क से समझौता किया जाता है। संगठन के युवा सदस्यों के विचारों और चिंताओं को अक्सर अनदेखा किया जाता है और यहां तक कि दबा दिया जाता है। यह संगठन के भीतर गुटबाजी को

रास्ता देता है। काफी कुछ स्वैच्छिक संगठन नेतृत्व की दूसरी पंक्ति की अनुपस्थिति से पीड़ित हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्य करने की शैली नेताओं के निर्माण और स्वस्थ संगठनात्मक मानदंडों को विकसित करने की योजना का संकेत नहीं देती है।

- यह भी देखा गया है कि कई स्वैच्छिक संगठन लक्ष्य समूह की क्षमता को बदलने और विकसित करने और अपने स्वयं के नेताओं की पहचान करने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीण गरीबों के व्यवहार्य संगठनों को विकसित करने के प्रयासों की कमी एक कारण है कि कई दशकों से गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठन की उपस्थिति के बावजूद, जमीनी स्तर के संगठन वास्तव में सामने नहीं आए हैं।

  अच्छे जमीनी स्तर के स्वैच्छिक संगठन की अनुपस्थिति गरीब किसानों के वास्तविक सशक्तिकरण को प्रभावित करती है।

- एक कम वेतन संरचना और कैरियर सीढ़ी प्रदान करने में असमर्थता कई प्रकार की गतिविधियों के लिए आवश्यक योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों को भर्ती करने और बनाए रखने के लिए स्वैच्छिक संगठन की क्षमता को सीमित करती है। स्वैच्छिक संगठन के भुगतान किए गए श्रमिकों के पास अक्सर मिश्रित दृष्टिकोण होते हैं, कुछ वास्तव में रुचि रखते हैं और प्रतिबद्ध होते हैं, जबकि अन्य इसे एक बेहतर विकल्प उभरने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में देखते हैं। कैरियर की सीढ़ी की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप एक बड़ा कारोबार होता है। यह स्वाभाविक रूप से स्वैच्छिक संगठन के कामकाज को प्रभावित करता है।

- अभिलेखों और खातों का खराब रखरखाव और अभिलेखों और खातों के रखरखाव के माध्यम से संगठन-निर्माण पर ध्यान देने की कमी। परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता की भी कमी है।

- देश के विभिन्न भागों में स्वैच्छिक प्रयासों का असमान विकास एक और बाधा है। वास्तव में राज्य के आकार या इसकी आबादी और सक्रिय स्वैच्छिक संगठन की संख्या के बीच कोई संबंध नहीं है। देश के कई हिस्से, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्र, स्वैच्छिक संगठन की अनुपस्थिति के कारण पीड़ित हैं जो ऐसे संगठनों के माध्यम से योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन का उपयोग कर सकते हैं।

- स्वैच्छिक प्रयास को प्रोत्साहित करने की आधिकारिक नीति के बावजूद, स्वैच्छिक संगठन को नौकरशाही और राजनीतिक नेताओं से वास्तविक समर्थन नहीं मिलता है। स्वैच्छिक संगठन के दृष्टिकोण से जिला स्तर और उससे नीचे की एजेंसियों सहित सरकारी एजेंसियां विकास कार्यक्रमों पर अपनी शक्ति और एकाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बेहतर ज्ञान और विशेषज्ञता का दावा करते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर, स्वैच्छिक संगठन के प्रति इन सरकारी एजेंसियों का रवैया उदासीन है। वे बड़े कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठन को समान भागीदार के रूप में नहीं मानते हैं। राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर उनके बीच सबसे अच्छी समझ हो सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर, संबंध हमेशा प्रोत्साहक नहीं होते हैं। काम करने की शैली नौकरशाही बनी हुई है और उम्मीद है कि स्वैच्छिक संगठन

अनुदान प्राप्त करने के लिए सत्ता के गलियारों में अपनी श्रद्धा दिखाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह है कि वास्तविक जमीनी स्तर के संगठन हतोत्साहित हो जाते हैं और अनुदान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। बड़ी संख्या में लोग सरकारी फंडिंग पर निर्भर नहीं रहना पसंद करते हैं। हाल के वर्षों में सरकार से अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से कई नकली संगठनों की स्थापना की प्रवृत्ति रही है, जिन्हें अक्सर अन्य उद्देश्यों के लिए हटा दिया जाता है या डायवर्ट किया जाता है। अपने प्रभाव के माध्यम से वे अनुदान प्राप्त करने में सक्षम हैं, भले ही ये संगठन केवल कागज पर मौजूद हों। उनके बारे में प्रतिकूल प्रचार का असर वास्तविक संगठनों पर भी पड़ता है। अब यह सर्वविदित है कि कई राजनेता और राजनीतिक दल अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठन का उपयोग करते हैं। यह वास्तविक चिंता का विषय बन गया है।

1980 के दशक के मध्य में भारत की एक स्वैच्छिक परिषद की स्थापना और स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक आचार संहिता बनाने के लिए आधिकारिक और गैर-आधिकारिक दोनों तरह के कदम उठाए गए थे। इससे एक समन्वित नीति तैयार करने, सरकारी वित्त पोषण के लिए एजेंसियों के चयन की सुविधा, धन के दुरुपयोग को रोकने और स्वैच्छिक क्षेत्र, विशेष रूप से छोटी एजेंसियों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, इस विचार को कई स्वैच्छिक समूहों से मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि यह आशंका थी कि इससे स्वैच्छिक क्षेत्र का नियंत्रण और विनियमन होगा और, नौकरशाहीकरण में वृद्धि होगी, इस प्रकार हाशिए वाले समूहों के साथ काम करने वाले संगठनों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

13.8 स्वैच्छिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण

अब जब आप स्वैच्छिक संगठन की भूमिका, उनकी ताकत और उनकी कुछ समस्याओं से परिचित हैं, तो आपको कुछ उपायों को भी जानना चाहिए जो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए जा सकते हैं। इस खंड में हम स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के सुझावों पर एक नजर डालेंगे। उनके माध्यम से जाने के बाद, आप देख सकते हैं कि क्या आप अपना कुछ जोड़ सकते हैं।

- नेताओं को वचन और कर्म के माध्यम से स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए। उद्योगपतियों, पेशेवरों और अकादमिक समुदाय को इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। इससे उन्हें गरीबों की विकास समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी।
- नौकरशाही जिस तरह से स्वैच्छिक संगठन से निपटती है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कामकाज की एक विस्तार उन्मुख प्रोत्साहक शैली बहुत महत्वपूर्ण है।
- सहायता अनुदान कार्यक्रमों को स्वैच्छिक संगठन के बीच व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए और इन अनुदानों के लिए आवेदन करने में सहायता की जानी चाहिए क्योंकि उनमें से कई के पास इस संबंध में बहुत कम अनुभव है।
- सहायता अनुदान का प्रवाह प्रभावित होता है यदि उन्हें लेने के लिए कोई एजेंसियां नहीं हैं। इसलिए स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास उन राज्यों या क्षेत्रों में किए जाने चाहिए जहां स्वैच्छिक एजेंसियां मौजूद नहीं हैं।

- सहायता अनुदान की प्रणाली को सुव्यवस्थित और सरल बनाया जाना चाहिए। अनुदान समय पर जारी किया जाना चाहिए क्योंकि देरी सेवाएं प्रदान करने और कर्मचारियों को भुगतान करने में समस्याएं पैदा होती हैं।
- स्वैच्छिक संगठन को अपने स्वयं के संगठनात्मक संरचनाओं और प्रशासनिक क्षमता में सुधार करने के लिए एक सचेत प्रयास करना चाहिए, जिसमें खाते और हाउसकीपिंग शामिल हैं।
- उन्हें समस्या को हल करने और प्रेरक तकनीकों के लिए प्रासंगिक विषय वस्तु में स्वयंसेवकों की दक्षताओं को विकसित करना चाहिए। लोगों को प्रेरित करने और समुदाय क्षमता निर्माण करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।
- सेवाओं के दोहराव से बचने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठन के बीच अधिक समन्वय होना चाहिए। स्वैच्छिक संगठन की एक समन्वय परिषद सहयोग और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करने और सरकार के साथ संयुक्त रूप से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए उपयोगी होगी।
- स्वैच्छिक संगठन द्वारा एक स्पष्ट प्रशिक्षण नीति लागू की जानी चाहिए क्योंकि प्रेरणा पर्याप्त नहीं है। एक पेशेवर दृष्टिकोण हमेशा बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होता है।
- बड़े स्वैच्छिक संगठन को कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कार्मिक नीतियां विकसित करनी चाहिए।
- स्वैच्छिक संगठन के कार्यक्रमों को प्रलेखित और व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि समाज उनके प्रयासों का आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति में हो। यह दूसरों के लिए संसाधन सामग्री के रूप में भी काम करेगा।

अपनी प्रगति की जांच करें 3

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ख) पाठ के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर संक्षेप में चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

13.9 सारांश

स्वैच्छिक प्रयास की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह दर्शाता है कि एक समाज अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है। इस इकाई में, हमने स्वैच्छिक प्रयास की अवधारणा और इसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की। हमने देखा कि कैसे स्वैच्छिक संगठन न केवल उनके मूल और प्रायोजन के मामले में, बल्कि उनके वित्त पोषण, स्वायत्तता, कार्य करने की शैली आदि के मामले में भी गैर-सरकारी संगठनों से भिन्न होते हैं। हमने आपको ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक संगठन और

गैर-सरकारी संगठनों की विभिन्न पहलों से भी परिचित कराया है। इस संदर्भ में, हमने कपार्ट और डब्ल्यूसीडब्ल्यूबी जैसे राज्य सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों और हिंद स्वराज ट्रस्ट, सेवा, प्रदान, एसडब्ल्यूआरसी और टीबीएस जैसे स्वैच्छिक संगठन के साथ काम किया है। हमने नोट किया कि स्वैच्छिक प्रयास के लिए ताकत का मुख्य स्रोत प्रतिबद्धता और समर्पण, लचीलापन और स्थानीय जरूरतों का जवाब देने की क्षमता, समुदाय के साथ घनिष्ठ बातचीत और नवीनता है। हालांकि, स्वैच्छिक संगठन को फंडिंग, कुछ के हाथों में निर्णय लेने की एकाग्रता, भुगतान किए गए कर्मचारियों की अनाकर्षक सेवा शर्तों, नौकरशाही की उदासीनता और राजनेताओं और अन्य लोगों की व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए स्वैच्छिक संगठन का उपयोग करने की प्रवृत्ति के संदर्भ में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

13.10 मुख्य शब्द

1) **विस्तार शिक्षा** : यह अनौपचारिक शिक्षा को संदर्भित करता है जिसका अर्थ किसानों/समुदाय के लोगों को उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए शिक्षित/प्रशिक्षित/सूचित करना है। यह ज्ञान कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों में हो सकता है। विस्तार शिक्षा में लक्षित समूह की क्षमता के निर्माण के लिए एक प्रोत्साहक और विकासात्मक दृष्टिकोण है ।

2) **एसोसिएशन का ज्ञापन** : सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के पंजीकरण के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाता है।

3) **एनजीओ** : गैर-सरकारी संगठन। स्वैच्छिक संगठन भी गैर-सरकारी संगठन हैं लेकिन सभी गैर सरकारी संगठन स्वैच्छिक संगठन नहीं हैं। कुछ स्वैच्छिक संगठन सरकार द्वारा भी शुरू, प्रायोजित और गठित किए जाते हैं।

13.11 संदर्भ-सूची

पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी की उन्नति के लिए परिषद, (1999), वार्षिक रिपोर्ट, 1999-2000, कपार्टः नई दिल्ली।

गंगराडे, के.डी. (1987), भारत में सामाजिक कार्य के विश्वकोश खंड 1 में ''स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास''। कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारः दिल्ली।

भारत सरकार (1985). सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90। खंड 2, योजना आयोगः नई दिल्ली।

भारत सरकार (1990), वार्षिक रिपोर्ट, 1999-2000, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालयः नई दिल्ली।

ग्राम नियोजन केंद्र (1988), स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत करने के लिए एक हैंड बुक, ग्राम नियोजन केंद्रः गाजियाबाद।

राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (1981), ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका, एनआईपीसीसीडीः नई दिल्ली।

फर्नांडीस, वाल्टर (ईडी) (1986), स्वैच्छिक कार्रवाई और सरकारी नियंत्रण, भारतीय सामाजिक संस्थानः दिल्ली